

एसआईआर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बरसे स्टालिन

बिहार विवाद और हेमंत सोरेन के अलग होने की दिलाई याद

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विपक्ष के विरोध का समर्थन करते हुए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का विरोध कर रही है, लेकिन राज्यों में उसका रुख अलग है.

डीएमके ने बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे के विवाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अलग चुनाव लड़ने के फैसले का हवाला देकर विपक्षी एकता में समन्वय की कमी भी उजागर की.

एसआईआर के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने के

सीजेपी को दिया समर्थन विजय पर उठाए सवाल

डीएमके सांसद कनिमोड़ी करुणानिधि ने चेन्नई में प्रदर्शन के दौरान कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के गिरफ्तार नेताओं के प्रति समर्थन जताया. वहीं, डीएमके ने तमिलनाा वेंनी कड़गम (टीवीके) प्रमुख विजय से सवाल किया कि उन्होंने एसआईआर के खिलाफ स्पष्ट रुख क्यों नहीं अपनाया और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग का समर्थन क्यों नहीं किया.

एसआईआर का श्रेय लेने पर हुआ था विवाद

चेन्नई में डीएमके संसदीय दल की बैठक में स्टालिन की अध्यक्षता में पारित प्रस्तावों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनके आचरण की निष्पक्ष जांच कराने और एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संगठनों के आंदोलन का समर्थन करने की मांग की गई. पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक सुधारों पर भी जोर दिया.



कांग्रेस के दावे को डीएमके ने खारिज किया. पार्टी के मुताबिक, स्टालिन ने जुलाई 2025 में बिहार में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायतों के बाद ही इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी. उन्होंने बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा में भी हिस्सा लिया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 29 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ पार्टी के अभियानों को

तथ्यों पर आधारित बताया था. डीएमके ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का विरोध करती है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में उसका रुख उतना स्पष्ट नहीं रहा. पार्टी सांसद ए. राजा ने दावा किया कि डीएमके ने संसद और संसद के बाहर लगातार इस मुद्दे को उठाया तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क किया.

बिहार से गठबंधन की नसीहत

स्टालिन ने बिहार चुनाव के दौरान सीट बंटवारे में लचीलेपन की कमी और विपक्षी दलों के बीच तालमेल की समस्या का उल्लेख किया. डीएमके के अनुसार, कई सीटों पर राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के उम्मीदवार आमने-सामने थे . झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जेएमएम के अलग चुनाव लड़ने के फैसले को भी पार्टी ने गठबंधन की चुनौतियों का उदाहरण बताया .

पांच दिन में गई ट्रंप की प्रेस सचिव की कुर्सी

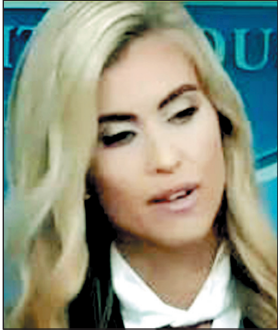
नवभारत नेटवर्क

वाशिंगटन, 17 अक्टूबर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव केटी जकारिया का कार्यकाल महज पांच दिन में खत्म हो गया. वह द वाल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दे रही थीं, तभी ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार स्टैफन मिलर ने पहुंचकर उन्हें बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी बस उनसे बात करना चाहते हैं. इसके कुछ ही देर बाद उन्हें पद से हटा दिया गया.

ट्रंप ने भी दी थी दोबारा सोचने की सलाह : इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने जकारिया से पूछा था कि

क्या यह नौकरी उनके लिए सही है. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने जकारिया को इस पद पर आने के फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह भी दी थी.

जकारिया की पहली आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग को



क्या यह नौकरी उनके लिए सही है. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने जकारिया को इस पद पर आने के फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह भी दी थी. जकारिया की पहली आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग को

एक नजर में

फार्मा कंपनी में भीषण आग पांच मजदूर झूलसे

भरवच . गुजरात के भरुच जिले के वागारा स्थित सायुजा औद्योगिक क्षेत्र (जीआईडीसी) की सिनजील फार्माकेम कंपनी में शनिवार को केमिकल प्रक्रिया के दौरान जोरदार धमाका हो गया. हादसे में पांच मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए . घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार कंपनी में हाइड्रोजेनशन प्रक्रिया चल रही थी . इसी दौरान अचानक विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि संयंत्र में लगी भारी मशीनरी के पुर्जे और लोहे के टुकड़े दूर तक जा गिरे . घटना के समय वहां काम कर रहे मजदूरों को सभलने का मौका तक नहीं मिला .

पाकिस्तान में सुरक्षाबलों की कार्रवाई

इस्लामाबाद . पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 10 लड़ाके मारे गए . शुक्रवार को औरकंडी जिले में चलाए गए इस अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने दो शव अपने कब्जे में लिए . वहीं प्रांत के पेशावर के पास एक पुलिस चौकी पर आतंकवादी हमले में कास्टेबल की मौत हो गई . दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है .

अंकिता भंडारी हत्याकांड में माता-पिता से मिली सीबीआई नई दिल्ली . उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की . सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया . अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां सोनी देवी ने दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मामले से जुड़ी विभिन्न जानकारीयां साझा की .

हस्तियों के ट्वीट

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि 'नेचर' में प्रकाशित नए शोध के अनुसार, मशीन लर्निंग की मदद से दो से छह सप्ताह पहले तक मौसम का पूर्वानुमान बेहतर बनाया जा सकता है . यह ऐसी अवधि है, जिसमें सटीक अनुमान लगाना अब तक बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक्स पर साझा पोस्ट में स्वीकार किया कि वे वैश्विक सम्मेलनों के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं हैं . उनके मुताबिक, ऐसे आयोजनों में चर्चाएं अक्सर अनुमान के मुताबिक ही रहती हैं . हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मना करना मुश्किल होता है और ब्लूमबर्ग समूह के संस्थापक माइक ब्लूमबर्ग उन्ही में से एक हैं .

सत्य नडेला

आनंद महिंद्रा

यूएस में इमिग्रेशन फीस बढ़ी

वर्क परमिट जुड़े आवेदनों पर पड़ेगा असर

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर. अमेरिका ने कुछ इमिग्रेशन सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है. अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के नए नियम 16 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं.

इसके तहत शरण के लंबित आवेदनों का वार्षिक शुल्क, रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (ईपीडी), अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) और कुछ इमिग्रेशन पैरोल सुविधाओं से जुड़े शुल्क बढ़ाए गए हैं. इसका असर उन भारतीयों पर भी पड़ सकता है, जो इन श्रेणियों के तहत आवेदन करते हैं. यह बढ़ोतरी सभी अमेरिकी वीजा पर लागू नहीं है. सामान्य पर्यटक वीजा और एच-1बी वीजा के शुल्क में इस अधिसूचना

अमेरिकी एजेंसी के अनुसार, शुल्क में बदलाव महंगाई के आधार पर किया गया है. जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2027 के लिए नई दरें तय की गई हैं.



के तहत बदलाव नहीं किया गया है. नए शुल्क उन संबंधित आवेदनों पर लागू होंगे, जिन पर 16 अक्टूबर या उसके बाद की डाक मुहर होगी. निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है. अमेरिकी एजेंसी के अनुसार, शुल्क में बदलाव महंगाई के आधार पर किया गया है. जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2027 के लिए नई दरें तय की गई हैं.

यूएन की रिपोर्ट पर भारत का पलटवार

लैंगिक न्याय पर दमन के दावों को किया खारिज

कहा- रिपोर्ट में अनाम और अपुष्ट बयानों का सहारा

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर. संयुक्त राष्ट्र में भारत ने युवाओं के अधिकारों और उनके विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर लगाए गए आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताया है.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक

कहा- बेबुनियाद आरोपों से संस्था की साख घटी

न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले युवाओं को प्रताड़ना या सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है. भारत ने आरोपों को अनाम और अपुष्ट प्रस्तुतियों पर आधारित बताते हुए रिपोर्ट तैयार करने के तरीके पर सवाल उठाए. संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में भारत के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है.

उन्होंने युवाओं के साथ सरकार के संवाद, परीक्षा में धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के प्रयासों का भी उल्लेख किया.

भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थित स्थायी मिशन के सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने बयान में इस प्रतिक्रिया की जानकारी दी. स्वरूप ने कहा कि विशेष प्रतिवेदक ने अपनी रिपोर्ट में कथित तौर पर अनाम प्रस्तुतियों का हवाला दिया है, जबकि आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण सामने नहीं रखे गए.

दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, 34 घटनाएं दर्ज

हिंदू संगठनों ने मांगी सुरक्षा, 11 मामलों में गिरफ्तारी का दावा

नवभारत न्यूज नेटवर्क

ढाका, 17 अक्टूबर. बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले मंदिरों पर हमले, देवी-देवताओं की मूर्तियां क्षतिग्रस्त करने और हिंसा की अन्य घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों ने चिंता जताई है. बांग्लादेश पूजा उद्‌जापन परिषद और महानगर सर्वजनियन पूजा समिति के अनुसार देश के अलग-अलग जिलों में ऐसी 34 घटनाएं सामने आई हैं.

संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सालभर प्रभावी व्यवस्था करने

मोदी के समर्थन में उतरे प्रवासी भारतीय

अमेरिकी गायिका मेरी मिलबेन ने भी किया समर्थन

सीजेपी को विदेशी फंडिंग मिलने का लगाया आरोप

नवभारत नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर. दिल्ली में तिरंगा रैली को लेकर सियासी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अमेरिका से ब्रिटेन तक आवाजें उठी हैं. लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर मोदी के समर्थन में नारे लगाए.

वहीं अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मेरी मिलबेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए भारतीय युवाओं से राजनीतिक स्थिरता के



पक्ष में खड़े होने की अपील की. लंदन में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा और प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मोदी को देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुना है और उन्हें जनादेश के अनुसार सरकार चलाने का अधिकार है. प्रदर्शन को कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई और अन्य समूहों की ओर से किए

जा रहे विरोध-प्रदर्शनों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. इस बीच, दिल्ली के कर्नाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के लिए जुटने की अपील के बाद शुक्रवार को पुलिस ने करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. इनमें सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल थीं.

8 साल पुराने केस में ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट

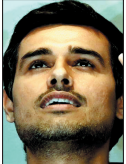
मानहानि केस में ध्रुव राठी को 31 अक्टूबर को कोर्ट में होना होगा पेश

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर. दिल्ली की साकेत अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि के करीब आठ साल पुराने मामले में जमानती वारंट जारी किया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन की अदालत ने राठी को 31 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है.

भाजपा आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे ने वर्ष 2018 में यह शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि

ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्हें रिश्तत देने की पेशकश करने से जुड़ी बात कही गई थी. पांडे का दावा है कि इस वीडियो से उनकी मानहानि हुई. मामले में राठी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अभी लंबित है. अदालत ने पांच दिन पहले, 12 अक्टूबर को भी राठी के खिलाफ नया समन जारी किया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने गौर किया कि शिकायतकर्ता लंबे समय से समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है.



कार्रवाई अनूप माझी के नेटवर्क पर कार्रवाई, दो होटल-रिसॉर्ट सहित संपत्तियां जांच के दायरे में

कोयला तस्करी सिंडिकेट की 136.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नवभारत न्यूज नेटवर्क

रांची, 17 अक्टूबर. अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनूप माझी उर्फ लाला के सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है.

एजेंसी ने 136.44 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर 815.08 करोड़ रुपये हो गया है. इससे पहले ईडी 678.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी थी. यह मामला ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(ईसीएल) के लीज वाले क्षेत्रों में कथित अवैध कोयला खनन, चोरी और उसकी बिक्री से जुड़ा है. ईडी की जांच के अनुसार, अनूप माझी के नेतृत्व वाला सिंडिकेट कथित तौर पर लंबे समय से इन क्षेत्रों से अवैध रूप से कोयला निकालकर पश्चिम बंगाल की विभिन्न फैक्ट्रियों में



नकद भुगतान लेकर बेचता था. एजेंसी को संदेह है कि इस नेटवर्क को चलाने में कुछ स्थानीय अधिकारियों की मदद भी ली गई थी. इन आरोपों की जांच जारी है.

दो होटल-रिसॉर्ट भी कुर्क

ताजा कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म और बांकुड़ा स्थित विहारीनाथ इको टूरिज्म नाम के होटल-रिसॉर्ट को भी कुर्क किया गया है. इसके अलावा कोलकाता में स्थित दो अचल संपत्तियां, जेकर कंपनियों के बैंक खातों में जमा रकम तथा माझी परिवार के सदस्यों के नाम

शेल कंपनियों के जरिए रकम छिपाने का आरोप

ईडी के मुताबिक कथित कोयला तस्करी से हासिल रकम को छिपाने और उसे वैध कारोबार का रूप देने के लिए कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया . ये कंपनियां अनूप माझी के रिश्तेदारों, कर्मचारियों और करीबी सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत बताई गई हैं . जांच में गुरुपद माझी का नाम भी सामने आया है . एजेंसी का आरोप है कि कोयले की अवैध बिक्री से प्राप्त नकदी को विभिन्न कंपनियों और बैंक खातों के माध्यम से धुमाया जाता था . इसके लिए कथित तौर पर अकमोडेशन एंटी का सहारा लिया गया, ताकि रकम के वास्तविक स्रोत और उसके लाभार्थियों की पहचान छिपाई जा सके . इसी इस वित्तीय नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है .

पर किए गए शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं . ईडी का मानना है कि इन संपत्तियों में कथित अपराधों से अर्जित धन का निवेश किया गया.

एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध कोयला कारोबार से प्राप्त रकम किन-किन लोगों और कंपनियों तक पहुंची तथा इसमें अन्य कौन शामिल रहे.